सोना-चांदी का सफर

निवेशकों को चौंकाने वाला रिटर्न

एक महीने के भीतर चांदी ने जो तेजी दिखाई उससे लंबे समय में जबरदस्त रिटर्न मिला

नई दिल्ली, 20 जनवरी. भारत में सोना और चांदी सिर्फ धातु नहीं, बल्कि परंपरा, सुरक्षा और निवेश का भरोसेमंद साधन माने जाते रहे हैं. बीते कई दशकों में इनकी कीमतों ने लंबा और उतार-चढ़ाव भरा सफर तय किया है.

महंगाई, आर्थिक संकट, युद्ध, वैश्विक मंदी और राजनीतिक अनिश्चितताओं के दौर में जब-जब दूसरे निवेश विकल्प डगमगाए, तब-तब सोना और चांदी निवेशकों के लिए सुरक्षित ठिकाने के रूप में उभरे. आज जब 24 कैरेट सोना रुपए 1.5 लाख प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच चुका है, तब यह सवाल स्वाभाविक है कि आखिर इसकी कीमत यहां तक कैसे पहुंची. आजादी के समय जहां 10 ग्राम सोने की कीमत सिर्फ रुपए 88 थी, वहीं 1990 के दशक में यह रुपए 3,200 के स्तर को पार कर चुकी थी. चांदी ने एक बार फिर निवेशकों को चौंकाते हुए नया इतिहास रच दिया है. 19 जनवरी को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी के दाम 3.02 लाख रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गए. महज एक महीने के भीतर चांदी ने जो तेजी दिखाई है, उसने न सिर्फ निवेशकों का ध्यान खींचा है, बल्कि बाजार के पुराने रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं. इसी तरह चांदी, जिसे कभी गरीब आदमी का सोना कहा जाता था, ने भी लंबे समय में जबरदस्त रिटर्न दिया है.

> वैश्विक स्तर पर 2008 के वित्तीय संकट के दौरान चांदी की कीमत में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया. संकट से पहले यह लगभग 20 डॉलर प्रति औंस थी, लेकिन घबराहट में हुई बिकवाली के चलते यह गिरकर करीब 9 डॉलर तक आ गई. इसके बाद 2010 और 2011 में चांदी ने जबरदस्त वापसी की और 2011 की पहली तिमाही में इसकी औसत कीमत 31.86 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई.

आर्थिक इतिहास के आंकड़े बताते हैं कि सोना-चांदी की कीमतों में आई तेजी केवल मांग का नतीजा नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक हालात, मुद्रा संकट और निवेशकों की मानसिकता का भी प्रतिबिंब रही है.

रुपया 11 पैसे टूटा, दूसरे निचले स्तर पर

मुंबई, 20 जनवरी. रुपया सोमवार को 11.25 पैसे टूटकर अब तक के दूसरे निचले स्तर पर आ गया और कारोबार की समाप्ति पर एक डॉलर 90.90 रुपये का बोला गया. भारतीय मुद्रा में यह लगातार चौथी गिरावट है. पिछले कारोबारी दिवस पर यह 44.75 पैसे लुढ़ककर 90.7875 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुई थी. चार दिन में यह 72.50 पैसे टूटी है. रुपये का ऐतिहासिक निचला स्तर 16 दिसंबर 2025 को दर्ज किया गया था जब यह बीच कारोबार में 91.14 रुपये प्रति डॉलर तक लुढ़कने के बाद 90.93 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था. रुपये में सुबह के कारोबार में तेजी रही. यह 10.75 पैसे मजबूत होकर 90.68 रुपये प्रति डॉलर पर खुला. यह ऊपर 90.65 रुपये प्रति डॉलर तक चढ़ने के बाद लुढ़कता हुआ 91.01 रुपये प्रति डॉलर तक उतर गया.

टैक्स सुधार सरकार की प्राथमिकता

बजट 2026 से पहले सामने आया रिपोर्ट कार्ड: निर्मला सीतारमण

1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करने की तैयारी

नई दिल्ली, 20 जनवरी. केंद्रीय बजट 2026-27 को पेश करने से पहले सरकार ने अपनी तैयारियों का संकेत देना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को एक तरह का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए पिछले बजट में किए गए अहम ऐलानों और उन पर अब तक हुई प्रगति की जानकारी साझा की.

टैक्स सुधार, निवेश को बढ़ावा और कर प्रणाली को सरल बनाने जैसे मुद्दे इस रिपोर्ट के केंद्र में रहे. सरकार का साफ संदेश है कि आने वाले बजट से पहले टैक्सपेयर्स और निवेशकों को भरोसा दिलाया जाए कि घोषित नीतियों को जमीन पर उतारा जा रहा है. न्यू टैक्स रिजीम में किए गए बदलावों से लेकर कॉरपोरेट टैक्स में दी गई रियायतों तक, वित्त मंत्रालय ने यह बताने की कोशिश की है कि कर सुधार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं हैं. ऐसे समय में जब आम करदाता महंगाई और बढ़ते खर्चों से जूझ रहा है, टैक्स देने के बाद हाथ में ज्यादा पैसा बचाने की नीति को सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है.

> केंद्र सरकार 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करने की तैयारी कर रही है. बजट से पहले वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को पिछले बजट में की गई प्रमुख घोषणाओं और उन पर अब तक हुई प्रगति का विस्तृत ब्यौरा साझा किया. इस रिपोर्ट कार्ड में टैक्स सुधारों को सबसे अहम उपलब्धि के रूप में रखा गया है. वित्त मंत्रालय के अनुसार, फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत न्यू टैक्स रिजीम में व्यक्तिगत आयकर ढांचे में बड़े बदलाव किए गए हैं. इन सुधारों का मकसद टैक्स सिस्टम को सरल बनाना और टैक्स चुकाने के बाद आम लोगों के हाथ में ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम छोड़ना है. मंत्रालय ने बताया कि ये सभी बदलाव वित्त वर्ष 2025-26 से लागू हो चुके हैं और इनका असर आकलन वर्ष 2026-27 से करदाताओं को दिखाई देगा.

दावोस से महाराष्ट्र को निवेश की बंपर सौगात

दावोस/मुंबई, 20 जनवरी. स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (डब्लूईएफ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन से महाराष्ट्र के लिए निवेश की बड़ी सौगात सामने आई है.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में महाराष्ट्र सरकार और मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने देश और विदेश की कई नामी कंपनियों तथा वैश्विक संस्थानों के साथ हजारों करोड़ रुपये के निवेश से जुड़े समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए. इन समझौतों से राज्य में औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है. सरकार के अनुसार, दावोस में हुए ये करार महाराष्ट्र को वैश्विक निवेश मानचित्र पर और मजबूत स्थिति दिलाने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं. रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स, स्टील, नवीकरणीय ऊर्जा, आईटी-आईटीईएस और डेटा सेंटर जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश से राज्य की अर्थव्यवस्था को लंबी अवधि में मजबूती मिलने की संभावना है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस दौरान उद्योग जगत के शीर्ष प्रतिनिधियों से मुलाकात कर महाराष्ट्र की निवेश-अनुकूल नीतियों और संभावनाओं को रेखांकित किया. विश्व आर्थिक मंच के दावोस शिखर सम्मेलन के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने कई अहम निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिन्हें राज्य के आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुए इन करारों में रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स, स्टील, नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी परिवहन, आईटी-आईटीईएस और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है.

उपेक्षित इलाकों में ऋण दें यूसीबी

मुंबई, 20 जनवरी. केंद्रीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों से उपेक्षित इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर ऋण देकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की अपील की है.

रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यहां चुनिंदा यूसीबी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ एक बैठक में कहा कि उपेक्षित इलाकों में ऋण देने में और वित्तीय समावेशन बढ़ाने में यूसीबी की महत्वपूर्ण भूमिका है. उन्होंने पिछली बैठक के बाद से सहकारी बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बैंक की पहलों के बारे में भी जानकारी दी. श्री मल्होत्रा ने विश्वास व्यक्त किया कि इन पहलों के परिणामस्वरूप यह सेक्टर मजबूत बनेगा और इसका स्वस्थ विकास होगा.

टैरिफ विवाद बढ़ा, भारतीय शेयर बाजार लुढ़का

नई दिल्ली, 20 जनवरी. वैश्विक स्तर पर बढ़ते टैरिफ तनाव का सीधा असर मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिला. अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच व्यापारिक शुल्क को लेकर बढ़ते गतिरोध ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है.

> मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे सत्र में गिरावट देखने को मिली. सुबह करीब 9:30 बजे, बीएसई सेंसेक्स 275 अंक या 0.33 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,971 पर कारोबार कर रहा था, जबकि एनएसई निफ्टी 91 अंक या 0.36 प्रतिशत फिसलकर 25,494 के स्तर पर आ गया. कमजोर वैश्विक संकेतों और अमेरिका-यूरोप के बीच बढ़ते टैरिफ तनाव ने निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता को प्रभावित किया. ब्रॉडकैप इंडेक्स भी बेंचमार्क के अनुरूप ही चले. निफ्टी मिडकैप 100 में 0.33 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.54 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. सेक्टोरल फ्रंट पर देखें तो निफ्टी एफएमसीजि, मेटल और पीयूएसयू बैंक को छोड़कर लगभग सभी सेक्टर लाल निशान में रहे .पीयूएसयू बैंक इंडेक्स 1.05 प्रतिशत की बढ़त के साथ टॉप गेनर रहा, जबकि रियल्टी और आईटी सेक्टर में क्रमशः 1.18 प्रतिशत और 0.65 प्रतिशत की गिरावट आई.

कमजोर ग्लोबल संकेतों और विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली ने घरेलू बाजार की धारणा को और कमजोर कर दिया. कारोबारी सत्र की शुरुआत से ही सेंसेक्स और निफ्टी पर बिकवाली का दबाव बना रहा, जिससे निवेशक सतर्क नजर आए. बाजार की यह कमजोरी ऐसे समय पर आई है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले से ही भू-राजनीतिक तनाव, ऊंची ब्याज दरों और धीमी ग्रोथ जैसी चुनौतियों से जूझ रही है. अमेरिका द्वारा यूरोप के खिलाफ नए टैरिफ खतरों ने अंतरर्राष्ट्रीय बाजारों में अनिश्चितता बढ़ा दी है. इसका असर एशिया-प्रशांत बाजारों पर भी पड़ा, जहां ज्यादातर प्रमुख सूचकांक लाल निशान में कारोबार करते दिखे.

हालांकि, इसी बीच अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत की एफवाई -26 जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत किया जाना एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है. इसके बावजूद, अल्पकालिक तौर पर बाजार की दिशा वैश्विक घटनाक्रम और विदेशी निवेशकों की गतिविधियों पर निर्भर करती नजर आ रही है.

दस फरवरी के बाद भी नहीं रद्द होगी उड़ान

नई दिल्ली, 20 जनवरी. चालक दल के सदस्यों की तैनाती में 'कुप्रबंधन' के कारण पिछले साल दिसंबर के पहले सप्ताह में बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द करने वाली निजी विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने नागर विमानन महानिदेशालय को बताया है कि उसके पास 10 फरवरी तक पर्याप्त संख्या में पायलट उपलब्ध होंगे और 10 फरवरी के बाद उड़ानें रद्द नहीं होंगी. डीजीसीए में पिछली साप्ताहिक बैठक के दौरान इंडिगो ने सोमवार को बताया कि उड़ानों की मौजूदा मंजूर संख्या के लिए डीजीसीए की फ्लाइट ड्यूटी से संबंधित छूट हटा लेने के बावजूद 10 फरवरी को पायलट की उपलब्धता को देखते हुए उड़ानें रद्द नहीं होंगी. उसने बताया कि 10 फरवरी को उसके पास एयरबस के 2,400 कमांड पायलट होंगे.

टाटा मोटर्स ने पोर्टफोलियो को किया अपग्रेड

नई दिल्ली, 20 जनवरी. देश की अग्रणी वाणिज्यिक वाहन कंपनी टाटा मोटर्स ने अपने पूरे ट्रक पोर्टफोलियो को अपग्रेड करते हुए मंगलवार को 17 नये ट्रक लॉन्च किये जिनमें पांच इलेक्ट्रिक ट्रक भी शामिल हैं.

टाटा मोटर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक गिरीश वॉग और उपाध्यक्ष तथा ट्रक कारोबार के प्रमुख राजेश कौल ने यहां भारत मंडपम् में इन ट्रकों की लॉन्चिंग की.

सिग्ना, प्राइमा, अल्ट्रा और ऑल न्यू अजूरा रेंज को बड़े पैमाने पर अपग्रेड किया गया है. ये ट्रक पहले के मुकाबले 1.8 टन तक ज्यादा भार ढोने की क्षमता रखते हैं और कंपनी का दावा है कि सात प्रतिशत तक कम ईंधन खपत के साथ अलग-अलग इस्तेमाल में ये 30 प्रतिशत तक ज्यादा मुनाफा देने में सक्षम हैं. श्री कौल ने बाद में यूनीवार्ता को बताया कि कीमतों की घोषणा अगले कुछ दिनों में की जायेगी. कंपनी ने अपग्रेड में सेफ्टी पर विशेष ध्यान दिया है.

विंग्स इंडिया में एयरबस तलाशेगी संभावित पदों के लिए उम्मीदवार

नई दिल्ली, 20 जनवरी. फ्रांस की विमान बनाने वाली कंपनी एयरबस विंग्स इंडिया 2026 में अपने विमानों और हेलीकॉप्टरों का प्रदर्शन करने के साथ संभावित तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों की तलाश भी करेगी. कंपनी ने बताया कि, वह 28 से 31 जनवरी 2026 तक हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित देश के प्रमुख एयरशो में एक इमर्सिव हेलीकॉप्टर सिम्युलेटर और अपनी एयरोस्पेस सेवाओं का पूरा पोर्टफोलियो प्रस्तुत करेगी.

समुद्री निर्यात पर भारत की वैश्विक पहल

नई दिल्ली, 20 जनवरी. भारत अपने समुद्री निर्यात को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक और व्यावसायिक प्रयास तेज कर रहा है. इसी क्रम में केंद्रीय मत्स्य विभाग 21 जनवरी को एक महत्वपूर्ण राउंडटेबल बैठक का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें 83 से अधिक देशों के राजदूत और उच्चायुक्त भाग लेंगे.

83 देशों के राजदूतों के साथ राउंडटेबल

निवेश और बाजार पहुंच पर जोर

यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब भारत समुद्री खाद्य निर्यात के क्षेत्र में दुनिया के प्रमुख देशों में शामिल हो चुका है और अब बाजार विस्तार, निवेश तथा मूल्यवर्धन पर जोर दे रहा है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत मछली और मत्स्य उत्पादों के निर्यात

में वैश्विक स्तर पर छठे स्थान पर है. वर्ष 2024-25 में समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात 16.98 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया, जिसका कुल मूल्य 62,408 करोड़ रुपये रहा. यह भारत के कुल कृषि निर्यात का करीब 18 प्रतिशत है. सरकार का मानना है कि बहुपक्षीय संवाद और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए इस क्षेत्र में और तेजी लाई जा सकती है.

पीएम सेतु कार्यक्रम पर चर्चा में 40 से अधिक कंपनियों ने लिया भाग

पुणे, 20 जनवरी. देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए स्थापित संस्थानों और आईआईटी को प्रोत्साहित करने के लिए घोषित पीएम-सेतु योजना को लागू करने के बारे में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तत्वावधान में पुणे में उद्योग जगत के साथ आयोजित परामर्श कार्यक्रम में 40 से विभिन्न क्षेत्रों की अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों ने हिस्सा लिया.

मंत्रालय की ओर से सजारी विज्ञप्ति के अनुसार इस परामर्श में महिंद्रा एंड महिंदा, टाटा ग्रुप, टाटा मोटर्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, गोदरेज और फिएट जैसी प्रमुख औद्योगिक कंपनियों और समूहों सहित वाहन, निर्माण, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, तेल और गैस, और नवीकरणीय ऊर्जा सहित 40 से ज़्यादा कंपनियों ने भाग लिया. इस दौरान हब-एंड-स्पोक -धुरी और परिधि आईटीआई मॉडल, विशेष प्रयोगजन इकाईयों के माध्यम से उद्योगों के नेतृत्व वाले संचालन, पाठ्यक्रम नवाचार, प्रशिक्षकों का उन्नयन रोजगार की संभावनाओं को मजबूत करने के विषयों पर चर्चा की गयी.

समाचार विशेष

'टीम हैदराबाद' ने सोलापुर में कांग्रेस का बिगाड़ा खेल

सोलापुर. सोलापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. भाजपा की प्रचंड लहर के बावजूद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएम आईएम) ने आठ कॉर्पोरेटर जीतकर भाजपा के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है.

वोटों के पोलराइज़ेशन में एआईएमआईएम को साफ़ तौर पर लाभ मिला, जबकि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की राजनीतिक ताकत में भारी गिरावट देखने को मिली. भाजपा की लहर के बीच एआईएमआईएम ने मुस्लिम बहुल इलाकों में अपने पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण करने में सफलता हासिल की. 2024 में सोलापुर सिटी सेंटर से उम्मीदवार फारूक शबदी ने पार्टी के भीतर चल रहे विवादों के चलते चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद ज़िला अध्यक्ष अशोक पठान को नगर निगम चुनाव की पूरी ज़िम्मेदारी सौंपी गई. फारूक शबदी और शौकत पठान के बीच चले तीखे राजनीतिक टकराव के कारण यह माना जा रहा था कि एआईएमआईएम सोलापुर में अपनी ज़मीन खो देगी, लेकिन पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए.

सोलापुर में 'हैदराबाद टीम' का असर- वार्ड 14 और 20 लंबे समय से (एआईएमआईएम) के गढ़ माने जाते हैं. इन मुस्लिम-बहुल इलाकों में पार्टी ने शुरुआती दौर से ही बढ़त बना ली और अंत तक निर्णायक दबदबा कायम रखा. विरोधी दलों की ओर से ज़ोरदार प्रयास किए गए, लेकिन मज़बूत संगठनात्मक ढांचा, स्थानीय नेतृत्व और मतदाताओं से सीधा संवाद एआईएमआईएम की जीत का आधार बना.

भाजपा को मिला राजनीतिक लाभ

पिछले टर्म में एआईएमआईएम के 9 कॉर्पोरेटर चुने गए थे, जबकि इस बार पार्टी को 8 सीटों पर जीत मिली. हैदराबाद से आई लगभग 50 सदस्यों की टीम ने ज़मीनी स्तर पर रणनीतिक काम करते हुए कांग्रेस के परंपरागत गढ़ में सेंध लगाई, हालांकि इसका सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ भाजपा को मिला. आने वाले दिनों में नगर निगम की बैठकों, नीतिगत फैसलों और अल्पसंख्यक मुद्दों पर एआईएमआईएमकी भूमिका और आवाज़ पहले से अधिक प्रभावशाली रहने की संभावना है.

51 का लक्ष्य, 25 पर अटकी भाजपा

अमरावती मनपा में अब 'किंगमेकर' की शर्तों पर बनेगा महापौर!

अमरावती. अमरावती मनपा चुनाव के परिणाम शुक्रवार को घोषित होते ही शहर की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. हालांकि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन अब चुनाव के बाद की राजनीति और महापौर पद को लेकर गुप्त लॉबिंग और रणनीतियों का खेल शुरू हो गया है.

महापौर पद के आरक्षण की घोषणा के साथ ही इसके लिए जमकर लॉबिंग चल रही है. चुनाव परिणाम के बाद नगरसेवक अपने-अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर आगे की रणनीति तय कर रहे हैं. खासकर अल्पसंख्यक वर्ग के चुने हुए नगरसेवकों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि वे किसके साथ जाएंगे और किसे साथ लेंगे.

इस बीच भाजपा ने 51 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था और इसके लिए 68 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था. हालांकि भाजपा को महज 25 सीटें ही मिल पाईं, फिर भी पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीतकर सत्ता की राह में अग्रणी होने का दावा किया है. सभी दलों को झटका भाजपा के अलावा सभी दलों ने बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था. इनमें कांग्रेस ने 74 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. इसके अलावा युवा स्वाभिमान ने 33, शिंदे गुट ने 72, राष्ट्रवादी अजीत पवार गुट ने 85, उबाठा ने 41, राष्ट्रवादी शरद पवार गुट ने 19, और एमआईएम, बसपा, वंचित, समाजवादी पार्टी ने भी जोरदार तैयारी की थी. हालांकि, परिणामों के बाद इन सभी दलों को अपेक्षाकृत कम सफलता मिली है.

महापौर पद के लिए रस्साकशी

चुनाव परिणाम के बाद अब सभी की नजरें महापौर पद पर टिक गई हैं. आरक्षण की घोषणा का इंतजार करते हुए, महापौर पद के लिए पर्दे के पीछे तेजी से हलचलों का दौर चल रहा है. राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, सबसे अधिक सीटें मिलने के कारण भाजपा को स्वाभाविक रूप से आघाड़ी माना जा रहा है, लेकिन आरक्षण, गठबंधन और संख्याबल पर निर्भर करेगा कि महापौर पद कौन हासिल करेगा. सत्ता स्थापना के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी चालें तेज कर दी हैं. महिलाओं का दबदबा मनपा चुनाव में महिलाओं ने स्पष्ट रूप से अपना दबदबा स्थापित किया है.

मणिपुर में सरकार बनाने की शर्त

इंफाल. मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के एक साल पूरे होने जा रहे हैं. अगले महीने एक साल हो जाएगा. लेकिन अभी तक भाजपा लोकप्रिय सरकार के गठन का फैसला नहीं कर पाई है.

अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. तभी सवाल है कि क्या राज्य में सरकार का गठन होगा या राष्ट्रपति शासन में चुनाव होगा? यह सवाल इसलिए है क्योंकि पहली बार यह सुनने को मिला की कुकी समुदाय भी सरकार गठन के लिए तैयार है. लेकिन उन्होंने इसके लिए शर्त लगा दी है. कुकी समुदाय की शर्त है कि मणिपुर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए.

इसका अर्थ है कि कुकी समुदाय के लोग दिल्ली की तरह का राज्य चाहते हैं, जहां विधानसभा हो लेकिन केंद्र शासित प्रदेश हो. उप राज्यपाल के पास जमीन और कानून व्यवस्था के मुद्दे रहें. एक पूर्ण राज्य को अर्ध राज्य में बदलने की बात हो रही है. असल में कुकी समुदाय को पता है कि आबादी के हिसाब से हमेशा मैतेई का बहुमत होगा और मुख्यमंत्री भी उसी का होगा. ऐसे में अगर मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश बन जाए तो कुकी और दूसरे अल्पसंख्यक समूहों को अपेक्षाकृत राहत होगी और मैतेई मुख्यमंत्री की वजह से उनको भेदभाव नहीं झेलना पड़ेगा.

विशेष | क्या था मुलायम फैमिली का सीक्रेट समझौता, क्यों नहीं बुझ रही बगावत की आग

प्रतीक ने निभाया, अपर्णा ने तोड़ा!

लखनऊ. समाजवादी पार्टी के संस्थापक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत राजनेता मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव के इंस्टाग्राम अकाउंट से की गई एक पोस्ट ने सूबे में हड़कंप मचा दिया. पोस्ट में कहा गया कि उनकी पत्नी और भाजपा नेता अपर्णा यादव ने जिंदगी तबाह कर दी है.

इस पोस्ट में अपर्णा को स्वार्थी महिला बताते हुए तलाक देने की बात भी कही गई. इस पोस्ट की सबसे दिलचस्प बात यह है कि अपर्णा यादव ने 19 जनवरी 2022 को बीजेपी की सदस्यता ली थी. पोस्ट की तारीख भी 19 जनवरी है. अब इसे महज संयोग कहेंगे या फिर सोचा.समझा कदम कहा जाए. क्योंकि अपर्णा के भाजपा ज्वाइन करने के ठीक तीन साल बाद 19 जनवरी को ही प्रतीक यादव ने अपर्णा से रिश्ता तोड़ने का ऐलान किया है.

प्रतीक यादव के इंस्टाग्राम अकाउंट से की गई इस पोस्ट के बाद चौतरफा बवाल मच गया. बवाल बढ़ा तो अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट का बयान सामने आया. जिसमें उन्होंने कहा कि प्रतीक यादव का इंस्टाग्राम अकाउंट किसी ने हैक कर लिया था. दोनों के बीच सबकुछ सही है. हालांकि, अमन की यह बात कितनी सही है इसका जवाब तो अमन के पास ही होगा.

सपा से क्यों अलग हुई अपर्णा – दूसरी तरफइस पूरे मामले के बाद कई पुराने सवाल फिर से ताजा हो गए हैं. सवालों में सबसे अव्वल यह कि अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी का साथ क्यों छोड़ा? 2022 विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा क्या हुआ था? मुलायम परिवार में 20.21 साल पहले हुआ वह समझौता क्या था, जो अमर सिंह ने करवाया था. प्रतीक उस समझौते पर अटल रहे तो अपर्णा क्यों नहीं. दरअसल मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना यादव की परिवार में एंट्री के साथ ही परिवार में बगावत शुरू हो गई थी. सूबे की सियासत में दिलचस्पी रखने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि तब अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम से बगावत कर दी थी. वह बेहद नाराज रहने लगे थे और मुलायम की हर बात अनसुनी कर रहे थे. उस दौरान पिता और पुत्र के बीच बढ़ती दूरियों को कम करने और परिवार को एक साथ लाने की जिम्मेदारी अमर सिंह ने उठाई थी.

डिंपल सा अधिकार चाहती थीं अपर्णा

प्रतीक यादव लगातार कहते हैं कि वो कभी राजनीति में नही आएंगे. हालांकि जब भी सवाल अपर्णा यादव के सियासी भविष्य को लेकर होता तो वह कहते कि इसका फैसला नेता जी यानी मुलायम सिंह यादव और खुद अपर्णा कर सकती हैं. एक पत्रकार की बेटी होने के चलते अपर्णा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा हमेशा से रही. वह फैमिली में बड़ी बहू डिंपल यादव की तरह पार्टी में आधिकार चाहती थीं. अपर्णा की इसी जिद की वजह से मुलायम सिंह यादव ने 2017 में अपर्णा को पार्टी का टिकट दिलवाया था, लेकिन अपर्णा चुनाव हार गईं. हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि वो चुनाव जीतें. जबकि अखिलेश यादव ने खुद लखनऊ कैंट सीट पर उनके लिए प्रचार किया था.